>

Title : Need to restore the quota of food grains under PDS in Uttarakhand.

**श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) :** सार्वजनिक वितरण प्रणाली, देश में और विशेषकर उत्तराखण्ड में खाद्यान्न का वितरण करने में असफल हो रही है। उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र में खेती नाम मात्र की है और आजीविका के साधन भी नहीं के बराबर है। इस कारण वहां की अधिकांश जनता सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर मिलने वाले खाद्यान्न पर ही निर्भर हैं।

सूखा, भारी हिमपात व आतावृÂिष्ट से यहां की फसलें बरबाद हो चुकी है और दूसरी ओर आवश्यक वस्तुओं गेहूं, चावल, चीनी आदि की कीमतें खुले बाजार में आसमान छू रही हैं। केन्द्र सरकार के द्वारा उत्तराखण्ड के खाद्यान्न कोटों में भारी कमी करने के कारण स्थिति और अधिक खराब हो गयी है। इस कारण गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के लिए जीवन का संकट खड़ा हो गया है।

* Treated as laid on the Table

अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के खाद्यान्न गोदाम खाली पड़े हुए हौ। गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों का राशन कोटा घटा दिया गया है और गरीबी रेखा के ऊपर जीवनयापन करने वाले लोगों का खाद्यान्न आवंटन बंद हो गया है।

इन परिस्थितियों में मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि अतिशीघ्र उत्तराखण्ड राज्य को अतिरिक्त खाद्यान्न् आवंटित करते हुए वहां के निवासियों को पूर्व की भांति खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए।